(c) The ex-factory prices of Maruti vehicles including excise duty, at the time of their introduction and the current prices are given below :—

	Old price (Month of introduction) (Rs.)	Current price (Rs.)
Maruti 800 Car (Standard)	47,500 (December 1983)	63,900
Maruti 800 Car (Deluxe)	79,000 (November 1984)	93,800
Maruti 800 Car (A/C)	62,200 (November 1984)	77,700
Maruti 800 V (Flat Roof Van)	47,500 (November 1984)	67,500
Maruti 800 V (High Roof Van)	49,250 (November 1984)	68,900
Maruti 800 V (A/C)	82,900 (June 1986)	82,900
Maruti Gypsy	83900 (December 1985)	94,900

(d) Foreign exchange spent on import of components from start of production upto end of October, 1986 was US $ 214.93 Million.

(e) Cumulative Indigenisation achieved is as follows:—

	Indigenisation
Car	53·8%
Van	62·7%
Gypsy	39·0%

(f) 50 SKD car kits have been exported to Bangaladesh realising foreign exchange of about US $ 150,000. 4 Cars, 6 Vans and 5 Gypsys have been exported to Nepal against rupee payment.

Production capacity of Maruti Udyog Limited

1851. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there are propsals to export different models of Maruti cars to other countries; and

(b) if so, what are the details of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (PROF. K. K. TEWARY): (a) and (b) 50 SKD Car kits have been exported to Bangladesh and 15 complete vehicles to Nepal. Possibilities of export to other countries including Hungary, Mauritius, Sri Lanka and Iran are being pursued by Maruti Udyog Limited.

ग्रामीण उद्योगीकरण के लिये भारत-सोवियत चर्चा

1852. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 के अंत में भारत के ग्रामीण उद्योगीकरण के संबंध में भारत और सोवियत संघ के विशेषज्ञों के बीच मास्को में हुई चर्चा की कोई रिपोर्ट तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां तो उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कृषि उद्योग के विकास के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं और इसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) उद्योग मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की है क्योंकि इसमें भारत में ग्रामीण उद्योगीकरण पर बातचीत करने के लिए 1985 के अन्त में भारतीय विशेषज्ञों के शिष्टमण्डल को सोवियत रूस नहीं भेजा था ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुटीर व लघु उद्योग

1653. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आर्थिक सामाजिक और नैतिक दृष्टि से कुटीर व लघु उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है ;

(ख) यदि हां, तो कुटीर व लघु उद्योगों के गांवों से तेजी से गायब होने तथा शहरों में आश्रय लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) सरकार किस प्रकार के कुटीर व लघु उद्योगों को गांवों में स्थापित करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां । 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में देश के भीतर औद्योगिक विकास के सामाजिक उद्देश्यों पर बल दिया गया है । इस औद्योगिक विकास में उद्योगों का क्षेत्रीय छितराव, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का संवर्धन और एकाधिकार की रोकथाम करना सम्मिलित है ।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है ।

(ग) लघु उद्योगों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । फिर भी विभिन्न प्रोत्साहन रियायतें और केन्द्रीय निवेश राजसहायता रियायती वित्त आदि जैसी तकनीकी और अन्य सुविधाएं विपणन मशीनों व उपकरणों की किराया खरीद प्रबंध व तकनीकी प्रशिक्षण और लघु उद्योग सेवा संस्थानों औजार कक्षों, फील्ड टैस्टिंग केन्द्रों और खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों आदि के माध्यम से जांच संबंधी सुविधाएं देकर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देती है ।

(घ) स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों आदि की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारें ग्रामों में उपयुक्त उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन देती हैं ।

Cracks in Sagar Samrat drilling rig of Oil and Natural Gas Commission

1854. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sagar Pragati jack-up rig used by ONGC suffered major cracks in its hull and leg in April, 1985 and it was sent to Dubai for repair work and the said repair work is being delayed by the attitude of the Government in not attending the same in quick succession;

(b) whether it is a fact that the Government has lost more than Rs. 30 crores due to the slackness; and

(c) whether the Government is taking any action against the officials who were responsible for the said loss?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) Cracks were detected in the legs of ONGC's jack-up